मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2021-23 /R.N.I. No. 2022007062

बच्चे की मैनहोल में मौत के जिम्मेदार हैं भ्रष्ट अधिकारी 2
विदेश जाने के लिए केवल अधिकृत एजेंट से ही करें सम्पर्क 4
विकल्प भी अगर हिंदुत्व है तो फिर भाजपा ही क्या बुरी है? 5
भाजपा जो फ़सल काट रही है, वह 'गीता प्रेस' ने तैयार की है 6
मॉडल संस्कृति स्कूल : ढोल के अंदर पोल ही पोल 8

वर्ष 37 | अंक 47 | फरीदाबाद | 25 जून-1 जुलाई 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ की बेहद कमी

मरीज व डॉक्टर दोनों भयंकर परेशान

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) मज़दूरों के वेतन से रुपयों का अम्बार लगा कर खुश होने वाला कॉर्पोरेशन केवल वेतन बचाने के लोभ में न तो पर्याप्त पैरामेडिकल और न ही नर्सिंग स्टाफ़ भर्ती कर रहा है। इतना ही नहीं जो स्टाफ़ रखा भी हुआ है वह भी नियमित न होकर ठेकेदारी में चल रहा है। ज़ाहिर है इसका दुष्प्रभाव यहां इलाज हेतु आने वाले मरीज़ों पर पड़ना स्वाभाविक है।

प्रति दिन 4000 से अधिक ओपीडी व 850 मरीज़ों को वार्डों में रखने वाले इस अस्पताल को कुल कितना स्टाफ़ रखना चाहिये, इसके लिये 'मज़दूर मोर्चा' ने अनेकों व्यापारिक अस्पतालों के अलावा दिल्ली स्थित एम्स का विस्तृत अध्ययन किया है। फिलहाल व्यापारिक अस्पतालों की तो बात ही छोड़ दीजिये क्योंकि उन्हें तो अपने ग्राहकों को पंचसितारा सेवायें उपलब्ध करानी होती हैं, यहां केवल भारत सरकार के एम्स की बात करते हैं।

दिल्ली स्थित एम्स की सभी ब्रांचों में प्रतिदिन करीब 10,000 से अधिक मरीज़ ओपीडी में आते हैं और 3,279 मरीज वार्डों में दाखिल रहते हैं। यह संख्या यहां के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से करीब चार गुणा है। अब देखिए कि एम्स में नर्सिंग स्टाफ़ व पैरामेडिकल स्टाफ़ की संख्या कितनी है। वहां स्टाफ़ नर्सों की संख्या 5560 तथा

पैरामेडिकल स्टाफ़ की संख्या 5520 है। यद्यपि वहां कार्यरत स्टाफ़ के अनुसार, कार्यभार के हिसाब से यह संख्या भी कम है, फिर भी यदि स्टाफ़ की इसी संख्या को आधार माना जाए तो फरीदाबाद का ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहां खड़ा है, देखने की जरूरत है।

एम्स में मरीजों की संख्या के अनुपात में यहां पर 1450 स्टाफ़ नर्स होने चाहिए। जबकि यहां पर कुल 238 ही तैनात हैं। पैरामेडिकल, जिसमें लैबोरेट्री टेक्नीशियन आदि शामिल हैं 260 होने चाहिए जबकि इस काम पर केवल 70 कर्मचारी लगाये गये हैं। ऑपरेशन थियेटर स्टाफ़ में सीएसएसडी स्टाफ़ में 260 तथा इतने ही टेक्नीशियन होने चाहिए। जबकि सीएसएसडी में कुल 50 तथा टेक्नीशियन 70 लगे हुए हैं। गौरतलब है कि सीएसएसडी स्टाफ़ का कार्य ओटी में इस्तेमाल होने वाले तमाम साजो-सामान को पाक-साफ करके इस्तेमाल योग्य बनाना होता है। जबकि टेक्नीशियन लोग सर्जन के लिये ओटी एवं मरीज़ को ऑपरेशन के लिये तैयार करने के साथ-साथ सर्जन की सहायता भी करते हैं। रेडियोग्राफ़र यानी एक्सरे, एमआरआई तथा अल्ट्रासाउंड आदि के लिये 100 लोग होने चाहिए। जबकि उपलब्ध केवल 40 हैं। इन मुख्य विभागों के अलावा अन्य छोटे-मोटे कामों के लिये जहां 800 लोग होने चाहिए वहां केवल 400 ही काम को घसीट रहे हैं।

किसी भी अस्पताल में पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ़ रीढ़ की हड्डी के समान होता है। डॉक्टरों द्वारा जांच एवं इलाज के साथ-साथ नर्सिंग एवं मरीजों से सम्बन्धित अन्य कामों के लिये पैरामेडिकल स्टाफ़ की सख्त जरूरत होती है। उसके अभाव में अनेकों बार तो डॉक्टरों के किये कराए पर भी पानी फिर जाता है। ऐसे में पीड़ित मरीज़ एवं उसके परिजन सामने दिखने वाले डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ़ को ही कोसते व भला-बुरा कह कर संतुष्ट हो लेते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि इस पूरी समस्या के लिये वे उच्चाधिकारी जिम्मेदार हैं जो उन्हें नजर नहीं आ रहे।

अस्पताल में पदों की संख्या को कम से कम रखने के लिये ईएसआई कॉर्पोरेशन ने अपने आप ही स्वीकृत पदों का एक ड्रामा रच रखा है। अब, जब यहां पर स्टाफ़ की भयंकर कमी को लेकर ज्यादा ही हो हल्ला मचने लगा तो बीते सप्ताह, मुख्यालय ने अस्पताल की स्टाफ़ सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने को कहा है। समझा जाता है कि अस्पताल प्रशासन ने इस बाबत अपना आकलन करके मुख्यालय को भेज दिया है। अब देखना यह है कि इसे स्वीकृत करने में मुख्यालय कितना समय बर्बाद करता है।

गौरतलब है कि ईएसआई कॉर्पोरेशन को, स्वयं स्वायत्त होने के चलते अपने नियम आदि बनाने के लिये किसी सरकारी विभाग के पास नहीं जाना होता। वह अपने नियम कायदे तथा पदों को स्वयं स्वीकृत कर सकता है। जब **'मज़दूर मोर्चा'** विभिन्न व्यापारिक अस्पतालों तथा एम्स का सर्वेक्षण करके मरीजों के अनुपात में स्टाफ़ की संख्या निकाल सकता है तो मुख्यालय में बैठ कर मोटी-मोटी तन्ख्वाहें डकारने वाले अफसरों को क्या आफत है? आफ़त बस यही है कि कॉर्पोरेशन के कोष में प्रति वर्ष होने वाली 10,000 करोड़ की वृद्धि कुछ कम हो जायेगी।

(संबंधित खबरें पेज तीन पर)

वायु शोधन के नाम पर 55 करोड़ डकार चुका नगर निगम

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) शहर में वायु प्रदूषण न होता तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, नगर निगम को 55 करोड़ रुपये डकारने को न मिल पाते। समाचारों के अनुसार इस प्रोग्राम के तहत नगर निगम को अब तक 55 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। शहर की जनता के साथ यह कितना भयंकर मज़ाक है। यह एक प्रकार से प्रदूषण फैलाने का पुरस्कार है जो नगर निगम को दिया गया है। यानी कि वायु प्रदूषण न होता तो वायु शोधन के नाम पर निगम को ये 55 करोड़ भी न मिले होते। जाहिर है कि यह प्रदूषण बना रहना जरूरी है ताकि इसके नाम पर पैसे डकारने को मिलते रहें।

प्रदूषण बड़े काम की चीज़ सिद्ध हो रहा है। इसके नाम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामक एक महकमा पूरे देश में चल रहा है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कर्मचारियों के लिये वेतन के अलावा मोटी कमाई का यह एक बड़ा जरिया है। प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर यह केवल वसूली करता है, कुछ अपने लिये कुछ सरकार के लिये। इसके अलावा प्रदूषण घटाने में इस विभाग का कोई योगदान नहीं है।

एक रिपोर्ट के अनुसार 'टेरी' (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) को भी प्रदूषण जांचने का काम सौंपा गया था। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सर्दी और गर्मी के मौसम में यहां निर्धारित मानकों से कही प्रदूषण अधिक रहता आ रहा है। 'टेरी' इस बात का भी अध्ययन कर रहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के गर्भ में क्या है? उनका उत्पत्ति स्थल समेत अन्य कारणों पर भी काम कर रहा है।

समझ नहीं आता कि जो चीज़ दिन के उजाले की तरह साफ़ दिखाई दे रही है उसे टॉर्च जलाकर ढूंढने की आवश्यकता क्या है? पिछले दिनों सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक कचरा जलाने से सम्बन्धित समाचार प्रकाशित किया गया था। इस तरह के समाचार बेशक यदा-कदा ही प्रकाशित हो पाते हैं जबकि यह काम नित्य प्रति शहर के विभिन्न स्थानों पर हो रहे होते हैं। इसके अलावा सर्दियों में गरीब लोग आग तापने के लिये भी कूड़ा-कचड़ा जलाते हैं। इतना ही नहीं महंगी रसोई गैस न खरीद पाने वाले लोगों द्वारा जलाये जाने वाले ईंधन का धुआं, गरीब बस्तियों पर साफ देखा जा सकता है, सर्दियों में खासतौर पर।

टूटी व गड्ढेदार सड़कों से धूल तो बेतहाशा उड़ती ही है वाहनों में तेल भी अधिक फुकने से दोहरा वायु प्रदूषण होता है। इसके साथ-साथ सड़कों पर लगने वाले जाम से भी वाहनों का धुआं प्रदूषण में अच्छी-खासी बढ़ोतरी करता है। चलने के लिये बनी अच्छी-खासी सड़कों पर अवैध पार्किंग व कब्जों के चलते शहर में जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़कों की विधिवत सफाई न होने तथा किनारे पड़ी मिट्टी भी वाहनों के चलने से वायुमंडल में घुल जाती है। ये धूल-कण इतने महीन होते हैं कि एक बार वायु मंडल में चढ़ जाने के बाद तब तक नहीं उतर पाते जब तक बारिश न हो जाए। इसी तरह के धूल-कण पत्थर पीसने वाले क्रैशरों से भी भारी मात्रा में उड़ते है। भवन निर्माण

हवा साफ करने की नौटंकी

में नियमों का पालन न करने से बड़ी मात्रा में धूल-कण वायु में समाते रहते हैं।

औद्योगिक इकाइयां व ईंट-भट्ठे आदि भी सस्ते ईंधन का प्रयोग करते वक्त प्रदूषण की अनदेखी करते हैं। पकड़े जाने पर ले-दे कर छूट जाते हैं। इसका स्थाई समाधान खोजने की अपेक्षा शासन-प्रशासन केवल वसूली के द्वारा ही समस्या का समाधान करना चाहते हैं।

यही वे कारण हैं जिनके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण स्तर दिन-प्रति-दिन बढ़ता जाता है। अब समझ नहीं आता कि ये सब चीजें देखने के लिये सरकारी महकमे क्या अध्ययन कर रहे हैं? इसके अलावा नगर निगम कौन से टीनोपाल से वायुमंडल को धो-मांज कर साफ़-सुथरा कर रहा है?